पंचम माला, खंड 9 अंक 18 मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1971/16 अग्रहायण, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. IX, No. 18 Tuesday, December 7, 1971/Agrahayana 16, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

5th LOK SABHA DEBATES

(तीसरा सत्र)

(Third Session)

[खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 18, मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1971/16 अग्रहायण, 1893 (शक)
No. 18, Tuesday, December 7, 1971/Agrahayana 16, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
रक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य के बारे में	Re. Statement by Defence Minister ...	1
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paper laid on the Table ...	1
रेलवे अभिसमय समिति	Railway Convention Committee ...	2
अंतरिम प्रतिवेदन	Interim Report ...	2
पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प—	Statutory Resolution re. Continuance of Proclamation in respect of the State of West Bengal— ...	2—10
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda ...	2—3
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ...	3—4
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi ...	4
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar ...	5
श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C. T. Dhandapani ...	6—7
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami ...	7—8
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi ...	8—9
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin ...	9—10
अनुदानों की अनुपूरक माँगें (रेलवे), 1971-72-	Demands for Supplementary Grants (Railway), 1971-72— ...	10—20
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya ...	10
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb ...	11—12
श्री पी० वैंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah ...	12—13
श्री के० बालतन्डायुतम	Shri K. Balethandayutham ...	13—14
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Naval Kishore Sinha ...	14—15
श्री भागवत झा आज़ाद	Shri Bhagwat Jha Azad ...	15
श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C. T. Dhandapani ...	15—16
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma ...	16—17

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda ...	17
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai...	17—18
श्री आर० बी० स्वामिनाथन	Shri R. V. Swaminathan ...	18
श्री बनमाली पटनायक	Shri Banmali Patnaik ...	18—19
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra ...	19
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen ...	19—20
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	20
भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य—	Statement re. latest position about Pakistani aggression on India— ...	20—22
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram ...	20—22

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1971/16 अग्रहायण, 1893 (शक)
Tuesday, December 7, 1971/Agrahayana 16, 1893 (Saka)

लोक सभा दस बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

रक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य के बारे में

Re. STATEMENT BY DEFENCE MINISTER

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि रक्षा मंत्री सदन के स्थगित होने से पहले एक बजे एक वक्तव्य देंगे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लेखे

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1968-69 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—1235/71.]

रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

अन्तरिम प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं रेलवे अभिसमय समिति, 1971 का अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF THE STATE OF WEST BENGAL

अध्यक्ष महोदय : सदन अब श्री मोहसिन के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा ।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : श्री भट्टाचार्य ने कल कहा था कि पश्चिम बंगाल के लोग राष्ट्रपति-शासन के पक्ष में नहीं हैं । पश्चिम बंगाल की असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति-शासन के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । उन्होंने पुलिस की ज्यादतियों के बारे में भी शिकायत की । यह शिकायत आंशिक रूप में ठीक भी हो सकती है । पुलिस को शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये दृढ़ कार्यवाही करनी चाहिए । पश्चिम बंगाल के कुछ सरकारी कर्मचारी नौकरी से निकाले गये । इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो राजनीतिक तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग लेते थे । मैं तो कहता हूँ कि शेष ऐसे कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाला जाना चाहिए, जो राजनीति में भाग लेते हैं ।

पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले भारी बाढ़ आयी थी । नरसिंहगढ़, रूबंग, पिंगला, भगवानपुर, पटासपुर, दासपुर, देहरा और केशपुर आदि क्षेत्रों को इस बाढ़ से काफी हानि हुई । जिन लोगों के पास जीविका के कोई साधन नहीं, वे भूखे मर रहे हैं । इन क्षेत्रों में शुरू किये गये राहत कार्य अपर्याप्त हैं । इन राहत कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिये । बाढ़ से वे मुख्य-मुख्य सड़कें भी खराब हो गयीं, जो मिदनापुर से छेरूआ, बाली चोंच से पिंगला और गोपीवल्लभपुर से पंडाचाचा होकर गुजरती हैं । इन सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए । बासपहाड़ी और झडगुआन नामक दूरस्थ क्षेत्रों में भी नई सड़कें बनायी जानी चाहियें ।

पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है । बंद पड़े एककों को चालू करने तथा संकटग्रस्त एककों को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार ने दस सूत्री कार्यक्रम प्रारम्भ किया है । लेकिन इससे बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी । जब तक सरकार कच्चा माल सप्लाई करने की गारंटी नहीं देती, तब तक कोई भी उद्योगपति पश्चिम बंगाल में उद्योग स्थापित करने के लिये तैयार नहीं होगा ।

वित्तीय संस्थायें संकटग्रस्त एककों को सहायता प्रदान नहीं करतीं। सरकार बंद पड़े उद्योगों को चालू करने के लिए कुछ कदम उठा रही है। लेकिन चालू उद्योगों को अधिक मजबूत बनाने के लिये क्यों कोई कदम नहीं उठाये जाते ?

जब भी कोई नई परियोजना शुरू की जाती है, तो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए उचित कदम उठायेगी।

सरकार ने करसावती तथा कलघाई नामक सिंचाई परियोजनायें हाथ में ली हैं, जिसके लिए गरीब किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। इन किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि गरीब किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए उचित कदम उठाये जायें। फरग्राम सब-डिविजन की डोलोंग नदी परियोजना सन् 1947 से अब तक कार्यान्वित नहीं की गयी, इसी प्रकार एक बाढ़ नियंत्रण योजना भी थी। मुझे आशा है कि इस योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा ताकि लोगों की बाढ़ से रक्षा हो सके।

***डा० रानेन सेन** (बारसात) : पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति राज्य की चर्चा में बोलते हुए मैं नागरिक सुरक्षा उपायों पर जोर दूंगा। कलकत्ता तथा निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा कार्य संतोषजनक नहीं हैं। यह सच है कि भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तानी वायु सेना पर किये गये सफल आक्रमणों से पश्चिम बंगाल के लोगों के अन्दर सुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है, लेकिन फिर भी नागरिक सुरक्षा कार्यों की गति तेज करना उचित होगा।

इस युद्ध के दौरान चीन के रवैये का पता नहीं लगा। यह बात बिना किसी संदेह के कही जा सकती है कि रूस ही भारत का सच्चा मित्र है। साम्राज्यवादी अमरीका के षडयंत्र-पूर्ण रवैये के बारे में आज दुनिया में कौन नहीं जानता। बंगला देश के बारे में भी अमरीका ऐसी ही नीति अपनायेगा। अत: पश्चिम बंगाल की सुरक्षा तथा चीन के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए हमें नागरिक सुरक्षा कार्यों को और तेज करना चाहिए।

अब तक बंद पड़े कारखानों को खोलना भी बहुत जरूरी है, जिससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। जिन सुरक्षा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, उन्हें फिर से नौकरी पर लिया जाये।

यदि पश्चिम बंगाल राज्य को मजबूत बनाना है तो राष्ट्रपति राज के दौरान सरकार की नीति लोगों को खुश रखने की होनी चाहिए। मुझे पता चला है कि बोनगाँव में कई लोग सीमा की गोलाबारी से घायल हुए तथा मरे। इन लोगों को युद्ध जोखिम बीमे के लाभ क्यों नहीं दिये जाते। इस सदन के हर सदस्य को यह बात जाननी चाहिये कि त्रिपुरा-असम सीमा पर हजारों लोग मारे गये या जख्मी हुए।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi version of English translation of speech delivered in Bangla.

पश्चिम बंगाल के लगभग एक लाख किसानों के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं। यदि हम किसानों से अधिक अन्न पैदा करने की आशा रखते हैं तो इनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों को शीघ्र ही वापिस लिया जाना चाहिये। प्रजातंत्रीय तथा कृषि आन्दोलनों के लिये गिरफ्तार लोगों तथा राजनीतिक बंदियों को भी रिहा किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में कारखाने के कर्मचारियों के बीच अधिकांश कर्मचारी पटसन के कारखानों में काम करते हैं। इन कर्मचारियों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की माँग की है। सरकार तो कारखानों के मालिकों का ही हित देखती आई है और कर्मचारियों की माँगों की ओर कोई ध्यान नहीं देती। क्या सरकार पटसन उद्योगों के कर्मचारियों की माँगों की ओर ध्यान देगी ?

बंगला देश को मान्यता देने के समाचार से पश्चिम बंगाल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी। युद्ध कार्यों के लिए सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है।

वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं और कई वस्तुयें काले बाजार में बिक रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कितने जमाखोर तथा चोरबाजारी करने वाले गिरफ्तार किये गये ? क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करेगी ?

***श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** (कलकत्ता-दक्षिण) : आज मातृभाषा में बोलते हुये मैं गर्वोन्नत अनुभव कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव सदन के सामने आया है। इस संबंध में तीन प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति और पश्चिम बंगाल की औद्योगिक समस्याएँ।

हमारे दल, सी० पी० एम० और सी० पी० आई० के कार्यकर्त्ताओं को यह बात समझ लेनी चाहिए कि यदि हम पश्चिम बंगाल में "सोनार बांगला" का आविर्भाव करना चाहते हैं तो हमें पश्चिम बंगाल में बन्दूकों और बमों के राज्य को समाप्त करना है। मुझे आशा है कि नई स्थिति में हम सहयोग तथा शांति से काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के लोगों के अन्दर यह बात बैठ गई है कि एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव कराना व्यर्थ है। नये चुनाव कराने से पहले राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्थिति को स्थायी बनाना उचित होगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की शान्ति व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। पश्चिम बंगाल के संकटग्रस्त उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्वास निगम की स्थापना की गई है। यदि पश्चिम बंगाल के उद्योगों को मजबूत बनाना है, तो बोर्ड में से पूँजीपतियों के प्रतिनिधियों को निकाल कर इसका पुनर्गठन अनिवार्य है।

पश्चिम बंगाल के किसान देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जोतदार तथा बड़े-बड़े जमींदार स्थिति का लाभ उठाकर अपनी पैदावार को छिपा रहे हैं। समय आ गया है जब हमें उदार दृष्टिकोण से मिलकर इकट्ठे काम करना चाहिए।

---

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi version of English Translation of speech delivered in Bengali.

***श्री शक्तिकुमार सरकार** (जयनगर) : पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंधी प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक मशीनरी को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के बारे में उठाये गये कदमों के लिए मैं राज्यपाल को बधायी देता हूँ। इस राष्ट्रपति शासन में लोगों ने चैन की साँस ली है। आज लोग बिना भय के गलियों और सड़कों में घूम सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि स्थिति बिलकुल संतोषजनक है। आज भी वहाँ पुलिस ज्यादती करती है। इस स्थिति में सुधार होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के उच्चाधिकारी जन-आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके, जो अब भी नौकरशाह का जीवन व्यतीत करते हैं। ये उच्चाधिकारी संसद सदस्यों के प्रति भी शिष्टाचार का व्यवहार नहीं करते।

जेल की दुर्घटनाएँ सचमुच लज्जाजनक हैं। जेल के अधिकांश अधिकारी आई० ए० एस० केडर के हैं, जिन्हें जेल संबंधी अनुभव नहीं हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान कम से कम 50 व्यक्ति पश्चिम बंगाल की जेलों में मारे गये हैं। इस स्थिति की ओर हमें तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

पिछले तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ रही है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि केन्द्र को पश्चिम बंगाल की बाढ़-स्थिति का सामना करने के लिए 70 से 80 प्रतिशत तक का व्यय सहन करना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार इस योग्य नहीं है कि इस व्यय को सह सके।

सुन्दरबन क्षेत्र के विकास के बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ। प्रधान मंत्री ने मेरे पत्र के उत्तर में लिखा है कि इस मामले पर विचार हो रहा है। लेकिन अब तक भी इस दिशा में कुछ नहीं हुआ।

मैं पश्चिम बंगाल सरकार तथा राज्यपाल से अपील करता हूँ कि सुन्दरबन के विकास हेतु शीघ्र विकास बोर्ड की स्थापना की जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ समय पूर्व हमने यह प्रथा आरम्भ की थी कि सदन में अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषा में बोलने की अनुमति केवल उन्हीं सदस्यों को दी जायेगी जो कि अपने भाषण की प्रति पहले से ही लोकसभा सचिवालय को दे देंगे। इस तरह यदि आप अचानक दूसरी भाषा में बोलना आरम्भ कर दें तो हमारे कर्मचारियों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। अभी बंगला देश को मान्यता दिये हुए केवल दूसरा ही दिन हुआ है, परन्तु हर सदस्य बंगला भाषा में ही बोल रहा है।

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Shajapur) : It is not necessary that a Member of this House should be educated. If an uneducated person can be a Member of the House, then he should be allowed to speak in his own language. This rule should be relaxed.

MR. SPEAKER : I do not agree with you. Only educated persons should come here.

---

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi version of English Translation of speech delivered in Bengali.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आपका विनिर्णय यह था कि यदि कोई सदस्य बंगला में बोलना चाहता है तो उसे दो घण्टे पहले इस आशय की सूचना देनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक पूर्व सूचना देने और भाषण की प्रति उपलब्ध करने का प्रश्न है यह बात सभी प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में समान रूप से लागू होगी ।

SHRI R. S. PANDEY (Rajnandgaon) : As regards Bengali language, we feel that this language has brought about a revolution. We are keen to listen to this language even if we do not understand it. I submit that under exceptional circumstances, you should permit the use of Bengali for a few days.

***श्री सी० टी० दंडपाणि** (धारापुरम) : गृह-मंत्रालय में उपमंत्री महोदय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के शासन को छः महीने की अग्रेतर अवधि तक लागू रखने के संबंध में जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसे अपना पूर्ण समर्थन देने से पूर्व मैं बंगाल और तमिल की संस्कृति के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूँ ।

आज राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रपति-शासन लागू कर देना आम बात बन गई है । जब किसी राज्य के लोग इस बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाते कि उन्हें किस राजनीतिक दल का शासन मंजूर है तो केन्द्र को विवश होकर वहाँ राष्ट्रपति-शासन लागू करना पड़ता है । यह बहुत अजीब बात है कि कुछ राज्यों में तो राष्ट्रपति-शासन का स्वागत किया जाता है परन्तु कुछ राज्यों में इसे लोगों की आकांक्षाओं का दमन कहा जाता है ।

देश में इस प्रकार के वातावरण को पनपने देने के लिए जो राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि यह प्रवृत्ति हमारे लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगी । राजनीतिक दलों को यह सोचना चाहिए कि वे लोगों का विश्वास किस प्रकार जीत सकते हैं । उन्हें अब यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वे और अधिक देर तक लोगों को धोखा नहीं दे सकते । अतः उन्हें लोक-कल्याण के कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए ।

पश्चिमी बंगाल में तेजी से बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखकर आज देश के सभी बुद्धिमान लोग हैरान हैं । यह स्थिति पैदा करने के लिए राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी कम नहीं है । मार्क्सवादी साम्यवादियों का विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान राइफलों और बन्दूकों के द्वारा किया जा सकता है । परन्तु उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई इस स्थिति में कोई भी विकासमय कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया जा सकता और न ही उसे पूरा ही किया जा सकता है ।

हमें यह बात समझ में नहीं आई कि भारतीय सिविल सेवा के एक सेवा-निवृत अधिकारी

---

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त करने के बाद भी वहाँ का कार्यभार एक केन्द्रीय मंत्री को क्यों संभाला गया है ? क्या यह व्यवस्था वास्तव में पश्चिमी बंगाल के लोगों की सहायता के लिए की गई है या केवल केन्द्र में सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक लाभ पहुँचाने के लिए ? क्या मंत्री महोदय पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास की देखभाल कर रहे हैं या वहाँ के राजनीतिक विकास की ? यह राजनीतिक युक्ति संवैधानिक रूप से अनुचित है । इससे देश की समस्याओं को पक्षपातपूर्ण ढंग से सुलझाने के रवैये को बल मिला है । सभी राजनीतिक दल अपने स्वयं के स्वार्थों के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों की मुसीबत तथा गरीबी से लाभ उठा रहे हैं परन्तु उन्हें यह बात सदा याद रखनी चाहिये कि उन्हें चुनावों में फिर जनता के सम्मुख जाना है और फिर उनसे यह प्रश्न पूछा जायेगा कि उन्होंने जनसाधारण के हितों के लिए क्या किया है ।

पश्चिम बंगाल में जो भी सरकार रही है, उसने वार्षिक योजनाओं तथा तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत दी गई धनराशि का पूर्णतया उपयोग नहीं किया है । इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की शासन व्यवस्था में अवश्य ही कोई गड़बड़ है । क्या यह पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति अन्याय नहीं है ? मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम राष्ट्रपति शासन के दौरान इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये तथा प्रशासनिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार किये जाने चाहियें ।

अन्त में, मैं सभी राजनीतिक दलों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें पारस्परिक प्रत्याभियोग को त्याग कर, लोगों के दुःखों का निवारण करने की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये । आज सम्पूर्ण भारत की अर्थ-व्यवस्था केवल 75 परिवारों के हाथों में केन्द्रित है । लोगों में असन्तोष और रोष फैला हुआ है । इसे समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को तुरन्त ही कार्यवाही करनी चाहिये अन्यथा सम्पूर्ण देश में हिंसा फैल जायेगी ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : आपके परामर्श का आदर करते हुये मैंने अपना भाषण अंग्रेजी में देने का निर्णय किया है ।

मैं श्री मोहसिन के संकल्प का समर्थन करता हूँ । आज देश की समूची आंतरिक स्थिति में जो परिवर्तन हो गया है, उसे दृष्टिगत रखते हुये हमारे पास इस बात के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के शासन की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दी जाये । विरोधी पक्ष के सदस्यों की तरह हम भी इस बात के लिए आतुर हैं कि यथासंभव शीघ्र पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय सरकार स्थापित की जाये । परन्तु मैं अपने मार्क्सवादी मित्रों से, जो सदा ही पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाने का शोर मचाते रहे हैं, अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे अपने ही हृदय में झाँक कर यह बतायें कि गत 5 वर्षों में तीन चुनावों के बावजूद पश्चिम बंगाल में एक स्थायी लोकप्रिय सरकार क्यों नहीं बना सके ?

इसके साथ ही, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे पश्चिम बंगाल तथा तमाम पूर्वी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की ओर अपेक्षित ध्यान दे । आज उग्रवादी तत्व पश्चिम बंगाल में आर्थिक एवं बौद्धिक गतिरोध पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं । साथ ही वे समूचे पूर्वी क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं । यही कारण है कि आज पश्चिम बंगाल में अव्यवस्था तथा गड़बड़ की स्थिति पैदा हो गई है ।

इतना ही नहीं, उग्रवादियों ने असम तथा पड़ौसी राज्यों में अव्यवस्था तथा गड़बड़ की स्थिति पैदा करने की धमकी भी दी है। यह सौभाग्य की बात है कि अभी तक उन्हें इस दिशा में सफलता नहीं मिली है। यदि हम पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था स्थापित करने में असमर्थ रहे तो इससे समूचे देश की अखंडता खतरे में पड़ सकती है।

यह प्रसन्नता की बात है कि श्री राय के भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। परन्तु मुझे लगता है कि यह शांति केवल अस्थाई है। जब तक पश्चिम बंगाल की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का कुछ स्थायी हल नहीं निकल आता तब तक यह स्थिति बिगड़ती ही रहेगी। सरकार को यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि नक्सलवादी गतिविधियाँ केवल कुछ शरारत पसंदों या गुंडों की ही नहीं हैं अपितु इन गतिविधियों के पीछे वे युवक भी हैं जिन्हें अपना भविष्य अन्धकारमय दिखाई पड़ता है। जब तक देश में इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा नहीं की जातीं, जिनमें कि हमारे देश के युवक यह अनुभव करने लगें कि उनकी इच्छायें और आकांक्षायें पूरी होने वाली हैं, तब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति हमारे लिए समस्या ही बनी रहेगी।

यह दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल और विशेषतया समूचा पूर्वी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है; और इसीलिए वहाँ अधिक निराशा है। कुछ सप्ताह पूर्व सीनेटर केनेडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने भी यही बात कही थी कि समूचे पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास की एक गहन नीति बनाई जानी चाहिये। इस क्षेत्र को अनिवार्य रूप से एक मिश्रित क्षेत्र के रूप में लिया जाना चाहिये। अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्रीय सरकार को कानून और व्यवस्था की समस्या और आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय करने चाहियें। आज सारे संसार की आँखें पूर्वी क्षेत्र पर लगी हुई हैं क्योंकि इस क्षेत्र की राजनीति से सम्पूर्ण एशिया की परिस्थितियों में परिवर्तन आ सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूँ।

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : In case one is to explain the policy of the present Government in one sentence, I would say "The Government is willing to strike but afraid to wind".

The political instability is the main reason for imposition of President's rule in a State. It has its origin in the practice of Members' defecting from one party to another. In West Bengal, there is not only political instability but also political chaos which necessitated President's rule.

Last time, when West Bengal was discussed, it was accepted by hon. Minister that there was an improvement in the situation. In case it is a fact then why West Bengal has not been listed among the States for which it was announced that elections will be held in February ? Are the elections held to suit the convenience of the ruling party ? The Government should clarify this issue.

It has been stated by Shri Goswami that the problem of West Bengal is a socio-economic problem. But is this problem not there in other States ? Are some other parts of

the country not backward ? But we do not find that much of violence in those areas as we find in West Bengal. So it is not the question of backwardness or starvation. It is the question of some parties believing in the ideology of violence and whenever such parties have influence, it is very easy to see Naxalite tendencies there. Therefore, the basic problem has not been taken into account.

We have seen that Communists have been divided into two parties, one the C. P. I. and the other C. P. I. (M) Was there any national cause for this division ? No, the party has been divided on the basis of ideology. I want to stress that poverty and starvation do not lead to violence and burning of literature.

There is a tendency to support those who are friends or who help the ruling party to continue in Government. This tendency is not good in the interest of the country. Once Muslim League was considerd to be dead horse, but it is again active; who has given life to it ? Now the Muslim League has become one of the allies of the ruling party. Once this party was also considered communal and was bracketted with R. S. S. But now its name has been dropped from that list. It has appeared in the newspapers that the activities of the R. S. S. are likely to be banned. I would like to emphasise that the R. S. S. is a national organisation and it comes forward to face every crisis in the country. There is none in the country who is against removal of poverty. Who opposed Government in bringing prosperity to the common people ?

It is the duty of Government to see that the law and order situation is restored in the state as soon as possible. The President's rule is no solution to the problem. We favour the idea that industrial peace should be restored in industries in the state. Steps should be taken to make the closed industries run. An atmosphere free from violence should be created which is favourable for social life and industrial development.

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में अपने सुझाव दिये हैं। आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन 29 जून, 1971 को लागू किया गया था। उस समय राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति बड़ी ही चिंताजनक थी। पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक मोर्चे की मिली-जुली सरकार के शासन काल में 2 अप्रेल, 1971 से लेकर 29 जून, 1971 तक की अवधि में 339 राजनीतिक हत्याएँ की गईं और 217 अन्तर्दलीय झगड़े हुए तथा पुलिस पर हमला किये जाने के 434 मामले हुए। इस समय वहाँ पर हिंसा अपनी चरम सीमा पर थी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों, भयंकर बाढ़ के अभिशाप तथा 75 लाख शरणार्थियों के आ जाने से वहाँ के प्रशासन में अनेक कठिनाइयाँ आ गई थीं।

पश्चिम बंगाल में स्थिति को सामान्य बनाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किये गये। समाज विरोधी अड्डों पर छापे मारे गये। लगभग 38,400 अपराधी और समाज विरोधी तत्व गिरफ्तार किये गये। लगभग 4,696 व्यक्तियों को कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया। उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद पकड़ा गया। नक्सलवादियों और अतिवादियों की हिंसक घटनाओं में भारी कमी हुई है ? हिंसक घटनाओं के कारण जो शिक्षा-संस्थाएँ बन्द हो गई थीं, वे अब पुन: खुल गई हैं। वहाँ स्थिति धीरे-धीरे सुधरती जा रही है। किन्तु अभी हमें अपने प्रयास जारी रखने हैं ताकि वहाँ स्थिति पूर्णत: सामान्य हो सके और विधि-व्यवस्था भी ठीक हो जाय। पश्चिमी

बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का कारण न केवल राजनीतिक अस्थिरता थी बल्कि वहाँ विधि और व्यवस्था का बिगड़ना भी था। अब वहाँ विधि और व्यवस्था सुधरती जा रही है। चुनावों के लिए भी कानून और व्यवस्था का ठीक होना आवश्यक होता है। इसीलिये हमें इस दिशा में प्रयास जारी रखने हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था पुनः ठीक हो जाये। इस प्रयास में हम सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी बन्द औद्योगिक एकक पुनः चालू हो जायें। हम यह बिल्कुल नही चाहते कि कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग राज्य से उठाकर अन्यंत्र ले जाये। 1 जनवरी, 1971 से 31 अक्तूबर 1971 तक की अवधि में 68 एकक पुनः चालू कराये गये जिनमें 37,843 श्रमिकों को पुनः रोजगार मिला। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने एक 16 सूत्रीय कार्यक्रम भी लागू किया है। हमें ऐसा प्रयास जारी रखना है, जिससे पश्चिम बंगाल में शान्ति बनी रहे और वहाँ औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति होती रहे। इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस संकल्प को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पश्चिम बंगाल के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जून, 1971 की उद्घोषणा को 26 जनवरी, 1972 से 6 महीने की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक माँगे (रेलवे), 1971-72

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1971-72

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं रेलवे की अनुपूरक माँगें 14 तथा 15 पेश करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि सभा उनको स्वीकार करे।

रेलवे मंत्रालय की वर्ष 1971-72 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक माँगे प्रस्तुत की गईं :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
14	नयी लाइनों का निर्माण—पूँजी और मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि	1,000
15	चालू लाइन निर्माण—पूँजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	30,06,000

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं रेल मंत्री का ध्यान हावड़ा-आमता शेवखोला लाइट रेलवे की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसके बन्द कर दिये जाने से ग्रामीण जनता को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय ने रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान यह आश्वासन भी दिया था कि इस रेलवे के बन्द होने से जितने कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं, उन्हें सरकार रोजगार देगी। किन्तु उसके कर्मचारी अभी तक बेरोजगार हैं। ससराम लाइट रेलवे के कर्मचारी भी कुप्रबन्ध के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। बोनगांव क्षेत्र में रेलवे लाइन को दोहरा किया जाना चाहिये जिससे सैनिकों का सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में आना-जाना सुगम हो सके। साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि धर्मनगर से अगरतला तक नई रेलवे लाइन शीघ्र बनायी जानी चाहिए। वहाँ लोगों को भारी असुविधा हो रही है। धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है। यातायात के अभाव में अत्यावश्यक वस्तुएँ वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं जिसके परिणामस्वरूप दूध, दाल, चावल, प्याज, मछली आदि की कीमतें दिनो-दिन बढ़ती जा रही हैं। सामरिक दृष्टि से भी यह कम महत्वपूर्ण नहीं है अत: इस लाइन के निर्माण का कार्य तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया के अनुसार अनुपूरक माँगों पर चर्चा के दौरान सामान्य चर्चा नहीं होती है। प्रक्रिया नियम 216 में स्पष्ट लिखा है :

> ''अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही समिति रहेगा जिनसे वे बने हों और जहाँ तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या इन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।''

श्री ए० पी० शर्मा : रेल मंत्री द्वारा रेल बजट प्रस्तुत करते समय कुछ आश्वासन दिये गए थे। यदि उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाता तो हम मामले को सभा में उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री दशरथ देव : मंत्री जी ने श्रमिकों पर हुए अत्याचार के बारे में कुछ वचन दिये हैं। बरौनी में कर्मचारियों की ओर से आन्दोलन किया गया था तथा काफी लम्बे समय तक वहाँ हड़ताल भी रही थी। इस संबंध में मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया गया तथा यह समझौता हुआ था कि जिन कर्मचारियों ने आन्दोलन में भाग लिया था, उन्हें नहीं सताया जाएगा परन्तु फिर भी उन व्यक्तियों को मुअत्तल कर दिया गया है तथा उनकी सेवा में व्यवधान कर दिया गया है। सरकार ने अपना वचन पूरा नहीं किया है। कर्मचारियों को तंग करने के इस रवैये को समाप्त किया जाना चाहिये। यह भी बड़े दु:ख की बात है कि नैमित्तिक श्रमिकों को जिनकी संख्या लाखों में है तथा जिनको नौकरी करते 12 अथवा 14 साल से अधिक हो गये हैं अभी तक नियमित घोषित नहीं किया गया है। उन्हें नियमति श्रमिक के रूप में रोजगार दिए जाने के वैध अधिकार से वंचित रखने के लिये रेलवे उन्हें केवल दो या तीन महीनों के लिए नौकरी में रखती

है और 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही उनकी छंटनी कर दी जाती है ताकि वह नियमित श्रमिकों के रूप में रोज़गार के पाने के अधिकारी नहीं बन सकें। श्रमिकों को इस प्रकार धोखा देने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं केवल अनुपूरक माँगों तक चर्चा को सीमित रखूँगा। इनमें से एक माँग मद्रास-विजयवाड़ा रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के बारे में है। काफी समय से यह मामला रेलवे मंत्रालय के विचाराधीन था। मुझे प्रसन्नता है कि अन्ततः मंत्री महोदय ने इस लाइन के विद्युतीकरण की माँग की है किन्तु मेरा निवेदन यह है कि मद्रास-विजयवाड़ा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण विजयवाड़ा से आगे तक कर दिया जाना चाहिए क्योंकि विजयवाड़ा लाइन देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में सम्पर्क बनाने वाली लाइन है।

जहाँ तक इस उद्देश्य के लिए कोई संस्था स्थापित करने का प्रश्न है, मुझे याद है कलकत्ता में रेलों के विद्युतीकरण के कार्य के लिए एक संस्था बनाई गई थी। परन्तु खेद है कि कुछ समय पहले यह संस्था बन्द कर दी गई जिसके परिणामस्वरूप कई तकनीशियन और मजदूर बेकार हो गये। मंत्री महोदय कृपा यह जानकारी दें कि जो संस्था अब स्थापित की गई है, वह कलकत्ता में कार्य कर रही संस्था का अंग होगी ? जहाँ तक बेलाडिल्ला–विशाखापत्तनम क्षेत्र में कोटावासला और किरनडूल के बीच रेलवे लाइन के नवीकरण का संबंध है इस रेलवे लाइन को बेलाडिल्ला से विशाखापत्तनम लौह अयस्क ले जाने के लिए बनाया गया था तथा जापानियों द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता दी गई थी। इस लाइन पर अब तक कुल यातायात 25 जी० एम० टी० से कम रहा है फिर भी रेलवे पटरियाँ काफी खराब हो गई हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि इस लाइन के इतनी जल्दी खराब हो जाने के क्या कारण हैं ? रेल लाइनों के खराब होने का कारण डिजाइन की गलती है या पटरियों की खराबी, मैं इस समय कुछ कह नहीं सकता।

इस लाइन का प्रयोग केवल लौह अयस्क को ढोने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह लाइन ऐसे क्षेत्र में बिछी है जहाँ अधिकांशतः आदिवासी लोग रहते हैं। रेलवे लाइन बनने से इन लोगों को अच्छी परिवहन सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस लाइन का प्रयोग यात्री-गाड़ी चलाने के लिए किया जाना चाहिए। गुंटकल से धर्मवरम तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि बंगलौर और सिकन्दराबाद को बड़ी लाइन से मिलाया जाना चाहिए। यह दो महत्वपूर्ण राज्यों की महत्वपूर्ण राजधानियाँ हैं। इन्हें मिलाने की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही है। इसके बन जाने पर कई महत्वपूर्ण नगरों को मिलाया जा सकेगा।

जहाँ तक त्रिवेन्द्रम–क्विलोन–एर्नाकुलम छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का संबंध है, मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि राजधानी एक्सप्रैस द्वारा सब राज्यों की महत्व-पूर्ण राजधानियों को केन्द्रीय राजधानी से मिलाने की उनकी योजना तभी लाभदायक सिद्ध होगी यदि छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाए।

इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि वह उन क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण करायें

जो पिछड़े माने गये हैं और जिन पर अभी तक कुछ विचार नहीं किया गया। इन पिछड़े क्षेत्रों में इस बारे में पहले जो सर्वेक्षण किये गये हैं अथवा विभिन्न राज्य सरकारों ने उनके बारे में जो सिफारिशें की हैं, उन पर शीघ्रता से आगे कार्यवाही की जानी चाहिए। जहाँ खनिज और वन के संसाधन काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, मंत्रालय को उनका प्रयोग सफलतापूर्वक करना चाहिए और इस प्रकार स्थानीय जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करता हूँ कि रक्षा मंत्री एक बजे एक वक्तव्य देंगे।

श्री के० बालतन्डायुतम (कोयम्बतूर) : अनुपूरक अनुदानों की माँगों में मैं मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा मद्रास से विजयवाड़ा तक विद्युतीकरण करने की योजना का स्वागत करता हूँ। देश के कुछ भागों में दोहरी लाइनें बिछाई गई हैं, इस बात का भी मैं स्वागत करता हूँ।

मद्रास और विजयवाड़ा के बीच की लाइन का विद्युतीकरण किया जाना है। हमें यह कार्य इस प्रकार करना है कि यदि आवश्यकता पड़े तो इसका विस्तार दिल्ली तक किया जा सके। हमारे पास बंगाल से सियालदह डिवीजन की लाइनों को दोहरा करने की पहले से ही कुछ योजनाएँ हैं। इस संबंध में जैसोर तक लाइन बढ़ाने की, जोकि सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व-पूर्ण है, आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में सामरिक महत्व के केन्द्रों को भी मिलाने का विचार किया जाना चाहिए।

जहाँ तक मद्रास-अरकोणम लाइन का संबंध है, मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई है कि इस लाइन में 37 दरारें हैं। यह भी पता चला है कि अल्ट्रासानिक रेल दोष संसूचक ने और भी 700 दोष निकाले हैं। क्या मद्रास और अरकोणम के बीच विशेष रेलों का प्रयोग तो इसके लिए जिम्मेवार नहीं अथवा कि सरकार ने अन्य लाइनों के दोषों का पता लगाने का प्रयास ही नहीं किया।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने रेलवे के इन विभागों की ओर ध्यान दिया है तथा इन पर पैसा लगाया है। अत: मैं इन अनुपूरक अनुदानों की माँगों का पूरा समर्थन करता हूँ।

मद्रास-अरकोणम लाइन उत्तर में बम्बई तथा दक्षिण में त्रिवेन्द्रम को मिलाती है। अत: इनमें से कई लाइनें अरकोणम पर अभिमुख हो जाती हैं और अरकोणम तथा मद्रास के मध्य की लाइन का, जिसका नवीकरण हो रहा है, विद्युतीकरण किया जाना चाहिए।

अनुपूरक अनुदानों की माँगों को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय का ध्यान केवल रेलों तथा लाइनों के नवीकरण की ओर रहा है। रेलवे में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर उन्होंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जीवन सूचकांक 228 बिन्दु तक पहुँच गया है अत: स्वाभाविक रूप से मँहगाई-भत्ते में वृद्धि होनी चाहिए। आज देश में आपात स्थिति है और रेलें संचार का महत्वपूर्ण साधन हैं तथा सीमाओं को देश के अन्य भागों से मिलाती हैं।

रेलों की अनुपूरक माँगों में रेलवे कर्मचारियों के लिए मँहगाई-भत्ते को बढ़ाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि रेलवे की इन अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर चर्चा के लिए 2 घण्टे का समय नियत कर लिया जाये क्योंकि यह विषय ऐसा है कि इसमें सभी सदस्यों की रुचि है तथा सभी, कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, अत: मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकें।

श्री के० हनुमन्तैया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि सदस्यों के सुझावों का उत्तर देने के लिए मुझे आधे घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए ताकि मैं उनकी शंकाओं का पूर्णत: समाधान कर सकूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: 2 घण्टे का समय चर्चा हेतु तथा अतिरिक्त आधा घण्टा मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए नियत किया जाता है।

SHRI NAVAL KISHORE SINHA (Muzaffarpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir I rise to support the supplementary demands of grants in regard to Railway. I will try to confine myslf only to those demands that have been brought forward by the hon. Minister.

First of all I wish to thank the hon. Minister for establishing the sovereignity of Parliament over Railway Board. I hope then the hon. Minister will pay more attention to the suggestion of the Members now.

In the past the ministers in the railway ministry have been changed very frequently. This should not be so as it effects the implementation of various schemes taken up by them.

In the matter of laying down of new railway lines as well as in the conversion of narrow gauge and meter gauge into broad gauge, priority should be given to those lines which create economic infra structure. In this respect I want to mention the names of Meghalaya, Assam, North Bengal and North Bihar.

North Bihar has been suffering a lot due to lack of power. Dr. K. L. Rao is ready to construct a thermal power station over there but this cannot be done unless broad gauge line is there.

The hon. Minister must be aware of the definition of strategy in Railways that includes not only the military strategy but economic strategy also. The hon. Minister can ask for financial assistance on account of economic strategy, and he will get it, I have no doubt about it.

There are large deposits of iron ore in Singhbhum area of Bihar, but it cannot be transported because of inadequacy of railway lines and the deplorable condition of roads. The hon. Minister should see that more lines are built there.

Recently there were floods in Bihar and due to lack of means of transport we could not even transport fodder from Punjab and Haryana.

Another difficulty which is experienced in Bihar is in regard to allotment of railway wagons. Last year 20,000 wagons were alloted but actually only 6000 wagons were provided

and that 100 on broad gauge. Government is prepared to give chemical fertiliser but wagons are not available. I wish to know why is there shortage of wagons when there is enough capacity in the country for their production, perhaps this flow is not smooth as Railway protection force has not been able to discharge their duties effectively. The Minister who is determined to improve the condition of railways should improve the working of that force and I hope the hon. Minister will take into consideration my suggestion.

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य इस विषय पर बोलने के इच्छुक हैं, अतः मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वह 5 मिनट से अधिक समय न लें ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : पिछले दिनों मंत्री महोदय ने इस सभा में घोषणा की थी कि वह भारत के राज्यों की राजधानियों को भारत की राजधानी के साथ मिलाना चाहते हैं और गाड़ियों को सीधी लाइनों पर चलाना चाहते हैं। यद्यपि मंत्री महोदय ने स्वयं इस पुल का उद्घाटन किया था परन्तु उस पर बने मार्ग को दोहरा नहीं किया गया है। नौकर-शाहों के विरुद्ध मंत्री महोदय द्वारा की गई कार्यवाही की हम प्रशंसा करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इसी प्रकार प्रत्येक मामले संबंधी फाइलें पढ़कर स्वयं अपने विवेक और आत्मा की आवाज के अनुसार ही कार्य करें। नौकर-शाहों की राय पर ही निर्भर न रहें; ये लोग आप को गुमराह भी करते हैं।

मंत्री महोदय ने चाहा था कि असम मेल कानपुर रुक कर कुछ यात्रियों को ले जाया करे परन्तु नौकरशाहों ने इसका विरोध किया। मैं जानना चाहता हूँ कि जब भागलपुर से फरक्का बैरेज तक इस लाइन पर असम मेल को 15 घण्टों की बचत हो गई है तो भी क्या कारण है कि यह गाड़ी भागलपुर होकर न जाए ? पूर्वी बिहार में क्यूल तथा भागलपुर के बीच एक विशाल आन्दोलन की तैयारी की जा रही है। लोगों में भारी असन्तोष फैला है। लोग रोज मुझे ज्ञापन भेज रहे हैं और मैं उन्हें आपको प्रेषित कर रहा हूँ। 6 दिसम्बर, 1971 को उनका "माँग दिवस" था। यदि आप इस आन्दोलन को रोकना चाहते हैं तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि असम मेल क्यूल तथा भागलपुर से गुजरे। इससे सभा को दिया गया आपका वचन भी पूरा होगा कि आप सभी राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ना चाहते हैं और साथ ही असम और बिहार को तेज चलने वाली गाड़ियाँ भी मिल जायेंगी। साथ ही इस प्रकार की घोषणा आप आज ही या एक दो दिन में कर दीजिये अन्यथा यह आन्दोलन नहीं रुकेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे पर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये और इसे प्राथमिकता देकर किया जाये। गंगा के उत्तर में उत्तर प्रदेश और भागलपुर को बड़ी परेशानी हो रही है। आप यह मत कहिये कि यह काम बहुत बड़ा है अथवा कठिन है। आप इसे कीजिये। हम हमेशा आपका समर्थन करते हैं। आप रेलवे बोर्ड के नौकरशाहों के चक्कर के मत आइये।

श्री सी० टी० दंडपाणि (धारापुरम) : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ कि उन्होंने त्रिवेन्द्रम से एर्नाकुलम लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य हाथ में लिया है। परन्तु यह देखा गया है कि सरकार नई लाइनें बिछाने अथवा परिवर्तित करने का कार्य राज-नीतिक दबाव में आकर ही करती है और अनेक महत्वपूर्ण कार्य छोड़ दिये जाते हैं।

तमिलनाडु में त्रिवेन्द्रम से मद्रास के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य भी शीघ्र ही हाथ में लिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय बड़ी देर से की जारही इस माँग की ओर ध्यान दें। साथ ही कोयम्बतूर तथा डिन्डीगुल के बीच भी बड़ी लाइन निर्मित की जानी चाहिये। निवेली के उद्योग समूह में 18,000 कर्मचारी कार्य करते हैं अतः सलेम तथा निवेली के बीच भी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये।

रेलवे विभाग अपने रेलवे कर्मचारियों के लिये सुविधाओं की ओर प्रायः अधिक ध्यान नहीं देता। कोयम्बतूर से कोई तीन मील दूर पोडानूर रेलवे स्टेशन पर प्रायः 18,000 कर्मचारी रहते हैं परन्तु एक लम्बे समय से उनकी पेय-जल की माँग पूरी नहीं की गई है। वहाँ 25 मील दूर से रेलगाड़ी से नित्य पेय-जल आता है जिसके लिए रोज 7,000 रुपये खर्च होते हैं। रेलवे के पास मेतूपलायम से कोयानूर तक एक पाईप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है जिससे कि बीच के स्टेशनों को भी जल मिल सके। मुझे आशा है कि रेल मंत्री इस प्रस्ताव को प्राथमिकता देंगे।

दूसरे, पोडानूर में हमारे युवक तकनीशियन ऐसे आधुनिक उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं जिन्हें पहले स्विट्जरलैंड तथा जापान से 75,000 रुपये की लागत से मंगाया जाता था और जिन्हें अब हमारे तकनीशियन केवल 10 या 15 हजार रुपये की लागत पर ही बना लेते हैं। परन्तु फिर इन तकनीशियनों को यह कार्य करने के लिए काफी बड़ा स्थान या भवन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसके अतिरिक्त पोडानूर में तमिल-माध्यम स्कूलों के लिए कोई भवन नहीं है और छात्रों को टूटे-फूटे शैडों में पढ़ाई करनी पड़ती है।

कोयम्बतूर-चमाराननगर बरास्ता सत्यमंगलम् रेलवे लाइन को भी तुरन्त चालू किया जाना चाहिए। अरोकोनम-चिंगलपेट तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिये। चुनावों के समय यह भी वायदा किया गया था कि तिरुनेलवेली से कन्याकुमारी तक भी शीघ्र ही रेल लाइन बिछाई जायेंगी।

रेलवे विभाग ने महानगर परिवहन प्रणाली में कुछ रुचि ली है तथा कलकत्ता और बम्बई के लिए काफी धनराशि भी स्वीकृत की गई है परन्तु मद्रास के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। न जाने इसके क्या कारण हैं ? मद्रास को भी तो इस योजना में शामिल किया जाना चाहिये था।

एक समाचार है कि रेल मंत्रालय मैट्रपलायम-ऊटी लाइन को समाप्त कर रहा है। न जाने क्यों ऐसा किया जा रहा है ? यहाँ तो सदस्यगण नई लाइनों की माँग करते हैं और हमारा यह विचित्र विभाग वर्तमान लाइनों को भी तोड़ने पर उतारू हैं। मंत्री महोदय फिर शिवता लाइन को भी क्यों नहीं तोड़ डालते ?

मैट्रपलायम रेलवे लाइन के साथ-साथ कोई 200 परिवार गत 50 से 100 वर्ष से रह रहे हैं। किसी भी सरकार ने उन्हें वहाँ से निकालने की नहीं सोची। मंत्री महोदय से भी मेरी प्रार्थना है कि वह उन लोगों को इन घरों से न हटाये।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : इन अनुपूरक माँगों का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय

को याद दिलाना चाहूँगा कि इन्होंने इस सभा में कुछ आश्वासन दिये थे, जिनमें दो आश्वासन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो यह कि वह प्रत्येक शुक्रवार को आधा दिन रेलवे श्रमिकों के मामलों पर लगायेंगे, परन्तु उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया है। दूसरे, उन्होंने कहा था कि वह प्रबंध में श्रमिकों के योगदान संबंधी एक विस्तृत योजना तैयार करेंगे। वह भी नहीं किया। मंत्री महोदय शीघ्र ही इन बातों की ओर ध्यान दें।

इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय का ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे की छोटी या मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा क्योंकि इससे तीन राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार तथा असम को लाभ पहुँचता है। इनसे पूर्व के रेल मंत्री ने यह आश्वासन दिया था। क्योंकि इस क्षेत्र में इन कार्यों के सीमावर्ती क्षेत्र भी आते हैं, इसलिए इसका महत्व सामरिक महत्व की लाइनों से भी कहीं अधिक है। अतः मंत्री महोदय इन तीनों राज्यों की समस्याओं को समझें।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान असम मेल के बारे में दिये गये भागवत झा आजाद के सुझाव की ओर भी पुनः आकर्षित करना चाहता हूँ।

अन्त में, मैं निवेदन करूँगा कि बिहार में अराह-ससराम लाइट रेलवे के संबंध में सर्वेक्षण किया गया था। मुझे इनके परिणामों का तो पता नहीं परन्तु मेरा अनुरोध कि मंत्री महोदय इस ओर यथेष्ट ध्यान दें। यह छोटी लाइन बड़ी लाभप्रद है और इसे बड़ी लाइन बना देने पर भी लाभ ही रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे की अनुपूरक माँगों का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : अनुपूरक मांगों के विवरण में परिवर्तित तथा नई निर्मित की जाने वाली लाइनों का तो वर्णन है परन्तु उत्तर सीमावर्ती रेलवे लाइन का कोई जिक्र नहीं है जो कि बोनोगाँव से असम तक तिनसुकिया तक आती है। मुझे आशा है कि रेल मंत्री तथा रेलवे बोर्ड इसके सामरिक महत्व को समझेंगे।

मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि मीटर-गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जायेगा परन्तु इसमें मेरे क्षेत्र की उत्तर सीमावर्ती लाइन को शामिल नहीं किया गया है। इसके कारण वहाँ आवश्यक वस्तुओं का आवागमन नहीं हो पाता है और इससे न केवल मेरे जिले पर बल्कि त्रिपुरा, मिज़ो पहाड़ियों तथा मणिपुर आदि जिलों पर भी असर पड़ा है।

लुम्डिग से बदरपुर तक त्रिपुरा और कचार की अत्यधिक महत्वपूर्ण लाइन की स्थिति में भी सुधार नहीं किया गया है। वहाँ रेलगाड़ियां, बैलगाड़ियों की रफ्तार से चल पाती हैं। इसके अतिरिक्त मेरे जिले की रेल लाइनों को भी परिवर्तित किया जाना चाहिये।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Morena) : I support these Supplemetary Demands. Mau in Madhya Pradesh has a cantonement and therefore, many people travel to Mau *via* Ratlam. Hence this line should be developed and the condition of waiting rooms

improved. The meter-gauge line there should be converted into broad-gauge. This line should be extended from Ratlam to Khandwa. Then the construction of railway lines in backward areas of Western Nimar & Ghard had not been completed. I do not know the reasons for delay in it. I want that the line upto Guna should be extended to Shivpuri and then linked to Makshi Dewas. This would increase the importance of this small area. Then there should be provision for the passenger to be able to reach Guna from Indore direct instead of *via* Ujjain to Dewas.

Peaple were very happy to hear the hon. Minister's statement that all the meter-gauge lines would be converted into broad-gauge lines. I request that the metre-gauge line from Gwalior to Shivpuri *via* Bamaur, Chora and Sabalgarh be converted into B. G. and be linked to Sawai Madhopur. This line needs immediate attention since it is dacoit infested area. The Government has recognised it a backward area and therefore it should be developed forth wiith. Similarly there has been massive demand that the Punjab Mail should stop at Morena. It would increase the income of the Railways.

The catering arrangement at the railway stations and in the trains also are very unsatisfactory. They call for drastic changes. The catering contracts should be given to cooperatives and not to private contractors who do not do this job themselves but get it done by others. These contractors gives bribe and secure dozens of contracts. The hon. Minister should look into it and improve there affairs.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् (मदुरै) : मुझे खुशी है कि सरकार ने त्रिवेन्द्रम-क्विलोन एर्नाकुलम मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया है। परन्तु साथ ही अपने विवरण में टेनकासी तथा क्विलोन के बीच वर्तमान मीटर गेज लाइन की अत्यधिक प्रतिबंधित क्षमता का वर्णन है। उसका क्या अर्थ है ? माल के यातायात के परिवहन में कठिनाई के कारण तो यह परिवर्तन किया जा रहा है परन्तु हम जानते हैं कि इस परिवर्तन के लिये कई अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं। परन्तु क्या सरकार इन स्थानों के बीच माल की ढुलाई का कार्य बन्द कर रही है ? यदि ऐसा होगा तो रेलवे विभाग एक बिल्कुल गलत काम करेगा। फिर यद्यपि कारूर से डिण्डिगुल तक लाइन को परिवर्तित करने का जिक्र है, परन्तु कारूर—डिण्डिगुल लाइन को मुदुरै से ट्यूटिकोरिन तक परिवर्तित करने का जिक्र स्पष्टीकरण ज्ञापन में नहीं है। जब सरकार मुदुरै तक लाइन को परिवर्तित कर रही है तो फिर उसे मदुरै से क्विलोन तक परिवर्तित करने में क्या कठिनाई है क्योंकि यह तो थोड़ा-सा फासला है। साथ ही मंत्री महोदय कन्याकुमारी को त्रिवेन्द्रम तथा आगे तिरुनेलवेली तक भी लाइन का विस्तार करने पर विचार करें।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार मद्रास-विजयवाड़ा लाइन का विद्युतीकरण करना चाहती है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ भारी यातायात है और इससे गाड़ियों के आवागमन में विलम्ब भी कम होगा परन्तु मेरा अनुरोध है कि यह विद्युतीकरण विल्लूपुरम् से आगे तिरुचिरापल्लि तक किया जाये। साथ ही जब तक सरकार मद्रास—त्रिवेन्द्रम से मद्रास बरास्ता तिरुचिरापल्लि तथा मदुरै तक की मीटर-गेज लाइन को तुरन्त बड़ी लाइन में परिवर्तित की जाये अन्यथा माल की आवागमन की समस्या हल नहीं होगी। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में भी नई लाइनें बिछाई जानी चाहियें। इस संबंध में लोगों की ओर से बड़ी भारी मांग है।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : मंत्री महोदय ने बचन दिया था कि उड़ीसा में बाँसपानी

से जाखपुरा तक नई लाइन बिछाई जायेगी। यह क्षेत्र ऊँचे किस्म के लौह अयस्कों, निकिल, मैंगनीज तथा क्रोम आदि की खानों से भरपूर है परन्तु संचार व्यवस्था के कारण विकसित नहीं हो पाया है। मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ कि वह शीघ्र ही पारादीप तक रेल लाइन बिछवा रहे हैं परन्तु इसे मुख्य लाइन से भी जोड़ा जाना चाहिए अन्यथा अयस्कों के परिवहन तथा निर्यात में बड़ी कठिनाई होगी। मुख्य लाइन से जुड़ने पर ढुलाई, उतराई आदि पर खर्च भी बहुत कम होगा।

परिवहन की सुविधा के लिए खान तथा धातु विभाग निगम ने बांसपानी से जेरूडी तक रेल लाइन बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि खान-संबंधी कार्य में परिवहन की कठिनाई न हो। इसी प्रकार जाखपुरा से डुबरी तक लाइन का भी प्रस्ताव है। इसके निर्माण के फलस्वरूप सड़क परिवहन पर होने वाले भारी खर्च की बचत हो सकेगी। जाखपुरा से बांसपानी तक का क्षेत्र संचार व्यवस्था के बिना विकसित नहीं हो सकता। इसलिए रेल संबंध का होना बहुत जरूरी है। यहाँ यातायात क्षमता भी बहुत है।

कलकत्ता पत्तन पर अयस्क संबंधी कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कार्य हल्दिया तथा पारादीप पत्तनों पर ही किया जायेगा।

बिहार का सिंहभूमि जिला भी लौह अयस्कों से भरपूर है। इसे भी रेल लाइन से संबंधित करना पड़ेगा।

मयूरभंज के भूतपूर्व महाराजा ने रूपसा से वंग्रापूसा तक तथा पर्लेकेमेडी के भूतपूर्व महाराजा ने भाऊपारा से गुनपुर तक छोटी रेलवे लाइन बनाई थी। अब चूँकि इन रेलवे लाइनों को चलाना लाभप्रद नहीं है अतः इनको बड़ी रेलवे लाइन में बदल देना चाहिए जिससे कि इस पूरे क्षेत्र का विकास हो सके। यह क्षेत्र मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र है तथा इन रेलवे लाइनों को रामगोडा आदि स्थानों से होकर निकालना चाहिए।

SHRI BIBHUTI MISHRA (Motihari) : I congratulate the hon. Minister for converting three metre gauge railway lines into broad gauge. I also suggest that the metre-gauge line between Samastipur and Narkatiagang *via* Muzaffarpur, Motihari in Bihar should be converted into broad-gauge line. Besides, the metre-gauge line between Motihari and Bagha should be converted into broad gauge line. In view of the Gandak Project, now it has become necessary to provide a broad-gauge line in North Bihar. I have written a letter to the hon. Minister but no reply has been received as yet.

Due to the non-existence of any direct railway line with Calcutta the price of Jute fell shortly in North Bihar. The people of this region are facing great difficulties. Therefore, Government should take necessary steps in the matter.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : रेलवे विभाग की कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुये मैं इसकी माँगों का समर्थन करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि इस समय रेलगाड़ियों द्वारा सैनिकों तथा सैनिक सामान को सुचारु रूप से लाया ले जाया जा रहा है तथा जनता को भी कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय कुछ लक्ष्यों की पूर्ति करने में सफल हुये हैं। गाड़ियों के आने जाने के समय में नियमितता आई है। इसके अतिरिक्त एर्नाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक की छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने के प्रस्ताव के कारण अतिरिक्त धन की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। यह माँग बहुत पहले की गई थी। और हमें सन्तोष है कि इस माँग को पूरा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 13 करोड़ रुपयों की माँग की गई है। मैं इस संबंध में यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़ी रेलवे लाइन के साथ-साथ कुछ अन्य व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता होगी। उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार करना है, वर्कशाप स्थापित करने हैं तथा वहाँ पर क्षेत्रीय मुख्यालय की भी स्थापना होनी है। अतः सरकार को इन आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

उस क्षेत्र में यातायात की अधिकता है तथा यह तथ्य सिद्ध भी हो चुका है। अतः इस क्षेत्र की स्थानीय जरूरत में वृद्धि होगी तथा उसको पूरा करने के लिए ये कदम उठाये जाने आवश्यक हैं।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : Government are demanding additional amount through supplementary demands for grants for constructing new railway lines. But it is surprising that Government intend to close metre gauge lines from Fatuha to Islampur and Arrah to Sahasram even though these lines are remunerative. I demand that these lines should not be closed. If the owners of these railway lines are not prepared to run them they should be taken over by the Government so that the employees are not rendered jobless.

Patna-Gaya railway line should be doubled in order to facilitate the people using this service. I also demand that the cases against the railway employees working at various places, Barauni, Dhanbad, Tatanagar, etc., should be withdrawn so that they may serve the country with a new enthusiasm.

भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. LATEST POSITION ABOUT PAKISTANI AGGRESSION ON INDIA

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : माननीय सदस्यों को 4 दिसम्बर को दोपहर बाद सभा में दिया गया मेरा वक्तव्य याद होगा। उस समय मैंने कहा था कि हमें भारी हानि पहुँचाने के उद्देश्य से पाकिस्तान के पूर्वनियोजित आक्रमण को विफल कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेनायें हमें हानि पहुँचाने और हमारी प्रतिरक्षा के सम्भावित कमजोर स्थलों का पता लगाने के लिए बार-बार तथा कृतसंकल्प प्रयास कर रही हैं। हम पाकिस्तान की आक्रमणकारी सैनिक मशीन को कुंठित करने का प्रयास कर रहे हैं।

पाकिस्तानी वायु सेना हमारे हवाई अड्डों पर आक्रमण कर रही है, परन्तु उनके द्वारा पहुँचाई गई क्षति नगण्य है। हमारे हवाई अड्डों को पहुँची क्षति की मरम्मत करली गई है और वे चालू अवस्था में हैं। पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा ली जाने वाली हवाई उड़ानों में धीरे-धीरे कमी हुई

है। हमारी वायु सेना द्वारा उनके हवाई ठिकानों को पहुँचाई गई क्षति का यह परिणाम है। आज तक हमने पाकिस्तान के 52 लड़ाकू हवाई जहाजों को नष्ट किया है और 4 अतिरिक्त हवाई जहाजों को क्षति पहुँचाई जाने की सम्भावना है। 3 पाकिस्तानी विमान चालक हमारी हिरासत में हैं।

हमारी वायु सेना गत दो दिनों से हमारे अग्रिम मोर्चों की हवाई सुरक्षा की ओर ध्यान दे रही है और स्थल कार्यवाहियों में पूरी-पूरी सहायता कर रही है। हमने पाकिस्तानी संचार व्यवस्था, सप्लाई भण्डारों और तेल प्रतिष्ठानों को छिन्न-भिन्न करने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किये हैं। हमने कुल मिलाकर 22 विमान खोये हैं।

पुंछ पर पाकिस्तान के बार-बार आक्रमणों को भारी क्षति के साथ खदेड़ दिया गया है। छम्ब क्षेत्र में भारी दबाव पड़ रहा है। हमने अपने सैनिकों को मन्नवर तवी नदी पर वापस बुला लिया है ताकि वे फिर से पूरी तैयारी कर सकें। इस नियोजित वापसी से पहले हुई लड़ाई में पाकिस्तानियों के 25 टैंक नष्ट हुये और उनके बहुत से सैनिक मारे गये। हम अखनूर तथा शकरगढ़ क्षेत्र में जवाबी दबाब डाल रहे हैं।

पाकिस्तानी सेना को डेरा बाबा नानक क्षेत्र से पीछे धकेल दिया गया है। रावी का पुल हमारे अधिकार में है। पाक सेना द्वारा हमारे क्षेत्र में पिछली ओर से घुसने के सारे प्रयत्न विफल कर दिये गये हैं।

अमृतसर क्षेत्र में अब पाकिस्तानी सीमा की कुछ सीमा चौकियाँ हमारे अधिकार में हैं। फिरोजपुर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को सेहजरा क्षेत्र से बाहर धकेल दिया गया है।

राजस्थान क्षेत्र में एक सशस्त्र पाकिस्तानी टुकड़ी ने रामगढ़ के आस-पास के क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न किया। इस टुकड़ी को लोंगावाला पर रोक दिया गया और इसका सफाया कर दिया गया। निश्चित रूप से 20 टैंक नष्ट कर दिये गये और 7 अतिरिक्त टैंकों को नुकसान पहुँचाया गया। हम सिंध में दो दिशाओं से प्रवेश करने में सफल हुये हैं। हमारी सेना कई स्थानों पर आगे बढ़ गई है और हमारी अग्रिम पंक्तियाँ नया छोड़ से 10 मील की दूरी पर हैं। हमने इस्लामगढ़ पर भी कब्जा कर लिया है।

पूर्वी आँचल में हमारी सेना मुक्तिवाहिनी के साथ मिलकर कार्यवाही कर रही है। हमारे दबाव के कारण पाकिस्तानी सेना पीछे हट रही है। आज प्रातः हमने जैसोर हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। कालीगंज के पश्चिम के सब क्षेत्रों से पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया कर दिया है। महिरपुर के बरास्ता जनिडा गोलदंघाट राजमार्ग को काट दिया गया है। पहाड़ी दिनाजपुर में हमारी सेना रंगपुर-बोगरा राजपथ की ओर बढ़ रही है। लाल मुनीरघाट को उसके हवाई अड्डे सहित कब्जे में ले लिया गया है। कुरीगांव, रंगपुर और दीनाजपुर के उत्तर के क्षेत्र को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से आजाद करा दिया गया है।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि दो दिन पहले अखुरा पर अधिकार कर लिया गया था। मालवी बाजार तथा ब्रह्मणबाड़ी के सामरिक महत्व के स्थानों को घेर लिया गया है। पाकिस्तानी

सेना द्वारा कल फेनी क्षेत्र को खाली कर दिया गया था तथा हमारी सेना की अग्रिम टुकड़ी अब चाँदपुर की ओर बढ़ रही है ।

बंगला देश में पाकिस्तानी वायु सेना को वस्तुत: समाप्त कर दिया गया है । हमारी वायु सेना ने वहाँ अपनी पूर्ण धाक जमा दी है। चिट्टागोंग, चलना, मंगला और खुलना के सैनिक महत्व के प्रतिष्ठानों पर समुद्र से गोलाबारी की गई है । पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी सेना तथा पश्चिम पाकिस्तान के समूचे जल सम्पर्क को तोड़ दिया गया है ।

माननीय सदस्यों को पता है कि 4/5 दिसम्बर की रात्रि को भारतीय नौसेना द्वारा साहसी आक्रमण किये गये हैं । दो पाकिस्तानी युद्ध पोतों को डुबो दिया गया है तथा एक को भारी क्षति हुई है । हमारी नौसेना कराँची बन्दरगाह के 15 मील के अन्दर तक चली गई है । उसकी गोला-बारी से बन्दरगाह प्रतिष्ठानों तथा तेल भंडार टैंकों को भारी क्षति हुई है । बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने एक पाकिस्तानी पनडुब्बी को डुबो दिया है ।

तीनों सेनायें पूर्ण समन्वय के साथ कार्यवाही कर रही हैं । उन्होंने अपनी कार्यवाहियाँ बहुत दक्षतापूर्ण की हैं तथा एक सेवा द्वारा दूसरी सेवा को पूर्ण समर्थन दिया गया है ।

6 दिसम्बर को 8 बजे प्रात: से 10 बजे प्रात: तक संयुक्त राष्ट्र संघ के विमान सी-130 को सुरक्षा प्रदान की गई । इसका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सका । नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि की प्रार्थना पर अब 7 दिसम्बर को 7 बजे प्रात: से 11 बजे प्रात: आई० एस० टी० तक संयुक्त राष्ट्र संघ के विमान को सुरक्षा प्रदान की गई है । गत रात 10 बजे के बाद से ढाका पर कोई हवाई हमला नहीं किया गया है ।

ढाका से यह समाचार मिला है कि ढाका हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विमान को क्षति पहुँची है । वायु मुख्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उस समय भारतीय वायुसेना के किसी विमान द्वारा वहाँ कोई कार्यवाही नहीं की गई है । संयुक्त राष्ट्र संघ को सलाह दी गई है कि वह विमान को हुई क्षति के बारे में ढाका में जाँच करे ।

मैं सभा की ओर से अपनी सशस्त्र सैनिकों की वीरता की प्रशंसा करता हूँ तथा उन्हें बधाई देता हूँ । वे बड़ी बहादुरी के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं और शत्रु को पराजित कर रहे हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 8 दिसम्बर, 1971/17 अग्रहायण, 1893 (शक) के दस बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Wednesday, the 8th December, 1971/Agrahayana 17, 1893 (Saka)

New India Printing Press, Khurja